विवरण "ख"
राजस्थान को आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

	1993–94	1994–95	1995–96
आई०आर०डी०पी०	4430.00	4393.00	2194.00**
जे०आर०वाई०			
पहला चरण	12961.33	14266.86	13231.00**
दूसरा चरण	4568.75	4568.75	1819.00
बी०ए०डी०पी०			
सामान्य	1905.74*	2044.00*	2386.00
आई०जी०एन०पी०	5200.00	6000.00*	6000.00
एन०आर०वाई०	379.60	361.55	322.35
यू०बी०एस०पी०	73.95	96.00	71.40
ई०ए०एस०	राज्य वार आबंटन नहीं किए जाते । 1993–94 और 1994–95 के लिए जारी धनराशि क्रमश: 4575 और 12375 लाख रुपये है ।		

आई०जी०एन०पी० –इंदिरा गांधी नहर परियोजना

*जारी

**केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय

रोजगार और बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन

7698. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995 पर आधारित रोजगार और बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अनुसंधान और विश्लेषण कार्य को तेज करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के सर्वेक्षणों के संबंध में श्रम ब्यूरो के परामर्श ऐसी रिपोर्ट जारी करने की कोई सीमा निर्धारित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) एवं (ख) वर्ष 1995 में रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएस एसओ) ने अपने 51वें दौर (जुलाई 94–जून 95) में बहुत ही कम प्रतिदर्श संख्या (थिन सेम्पल) के आधार पर रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी एक सर्वेक्षण किया है । अभी भी, उपरोक्त सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य प्रगति पर है । अत. विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कोई अनुसंधान तथा विश्लेषण कार्य नहीं करता है ।

(घ) एवं (ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्य के कार्यक्रम का मार्गदर्शन सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों वाली एक शासी परिषद्, जिसका अध्यक्ष गैर-सरकारी सदस्य होता है, द्वारा किया जाता है । यह परिषद् समंक विधायन तथा रिपोर्टों को प्रकाशित करने की समय सारणी निर्धारित करती है । इस समय रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट कुल मिलाकर लगभग दो वर्षों के अंतराल में निकाली जा रही हैं । शासी परिषद् में कभी-कभी श्रम ब्यूरो भी प्रतिनिधि होता है, परन्तु हमेशा नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Public Sector Projects under construction

7699. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of Public Sector Projects under construction and the investment involved; and

(b) 10 major public sector projects currently under construction where cost over run is more than 50 per cent?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) As on 1.1.95, 356 projects costing Rs. 20 crores and above with the total estimated cost of Rs. 1,30,523 crores are under construction.

(b) 10 projects which have maximum cost overrun and also cost overrun of more than 50 per cent with respect to the latest approved cost is given in the enclosed Annexure. (*See* Appendix 173, Annexure No 168).

Total investment in public sector projects

7700. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state the total investment in all the Public Sectors including projects under construction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

—